



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16042020-219066
CG-DL-E-16042020-219066

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 99]	नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 16, 2020/चैत्र 27, 1942
No. 99]	NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 16, 2020/CHAITRA 27, 1942

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

जांच शुरुआत अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 अप्रैल, 2020

मामला सं. एसी-01/2020

विषय : रूस के मूल के अथवा वहां से निर्यातित पोलिटेट्राफ्लूरोएथीलीन (पी टी एफ ई) के आयातों पर लागू पाटनरोधी शुल्क की कोरिया आर पी से निर्यातित पोलिटेट्राफ्लूरोएथीलीन (पी टी एफ ई) के आयातों द्वारा कथित परिवर्चना से संबंधित परिवर्चना रोधी जांच की शुरुआत
फा. सं. 07/07/2020-डीजीटीआर.—

1. मै. गुजरात फ्लूरोकैमिकल्स लिमिटेड (जिसे यहां आगे “आवेदक” भी कहा गया है) ने समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे अधिनियम भी कहा गया है) और उसकी उसकी समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे नियमावली भी कहा गया है) के अनुसार घरेलू उद्योग की ओर से निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे प्राधिकारी भी कहा गया है) के समक्ष एक आवेदन दायर किया है जिसमें यह आरोप लगाया गया है कि रूस (जिसे यहां आगे “संबद्ध देश” भी कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित पोलिटेट्राफ्लूरोएथीलीन (पी टी एफ ई) (जिसे आगे “विचाराधीन उत्पाद” अथवा “पीयूसी” या “संबद्ध वस्तु” कहा गया है) के आयातों पर लागू पाटनरोधी शुल्क को कोरिया गणराज्य (जिसे आगे “पीयूआई” भी कहा गया है) से निर्यातित पी टी एफ ई के आयातों के माध्यम से परिवर्चित किया जा रहा है।

क. पृष्ठभूमि:

2. निर्दिष्ट प्राधिकारी ने 13 अक्टूबर, 1999 की अधिसूचना सं. 21/1/1998 द्वारा रूस के मूल के अथवा वहां से निर्यातित पोलिटेट्राफ्लूरोएथीलीन (पी टी एफ ई) के आयातों पर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश करने वाले अंतिम जांच परिणाम अधिसूचित किए थे और दिनांक 30 दिसंबर, 1999 की अधिसूचना सं. 141/99-सीमाशुल्क द्वारा संबद्ध वस्तु पर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाया गया था।
3. प्राधिकारी ने 7 अक्टूबर, 2004 की अधिसूचना सं. 15/6/2003-डीजीएडी द्वारा पाटनरोधी शुल्क को जारी रखने की सिफारिश की थी जिसे पहली निर्णायक समीक्षा जांच के अनुपालन में दिनांक 18 नवंबर, 2004 की अधिसूचना सं. 110/2004-सीमाशुल्क के माध्यम से केन्द्र सरकार द्वारा लगाया गया था।
4. प्राधिकारी ने दिनांक 26 फरवरी, 2010 की अधिसूचना सं. 15/30/2008-डीजीएडी द्वारा पाटनरोधी शुल्क को जारी रखने की सिफारिश की थी जिसे दूसरी निर्णायक समीक्षा जांच के अनुपालन में दिनांक 3 मई, 2010 की अधिसूचना सं. 57/2010-सीमाशुल्क के माध्यम से केन्द्र सरकार द्वारा लगाया गया था।
5. प्राधिकारी ने दूसरी निर्णायक समीक्षा जांच के अनुपालन में दिनांक 12 अप्रैल, 2016 की अधिसूचना सं. 15/2/2015 द्वारा पाटनरोधी शुल्क को जारी रखने की सिफारिश की थी जिसे दिनांक 6 जून, 2016 की अधिसूचना सं. 23/2016-सीमाशुल्क द्वारा केन्द्र सरकार द्वारा लगाया गया था और दिनांक 16 मई, 2017 की अधिसूचना सं. 22/2017 द्वारा आगे संशोधित किया गया था। झूटी 5 जून 2021 तक लागू रहेगा।

ख. विचाराधीन उत्पाद

6. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद, जैसा कि अंतिम आयोजित सूर्यास्त समीक्षा जांच में परिभाषित किया गया है, "पॉलीटेट्राफ्लूरोएथीलीन (जिसे 'पीटीएफई' या 'विचाराधीन उत्पाद' के रूप में भी जाना जाता है) रूस से उत्पन्न या निर्यात किया जाता है। 5 जून, 2021 तक।
7. पी टी एफ ई को विभिन्न ग्रेडों में उत्पादित किया जाता है जैसे मोल्लिंग ग्रेड, फाइन पाउडर, एक्वस डिसपर्सन और फील्ड ग्रेडों के यौगिक ग्रेड। पी टी एफ ई को प्राथमिक रूप से उसकी अद्वितीय विशेषताओं के लिए इलैक्ट्रिकल, इलैक्ट्रॉनिक, मेकेनिकल और रासायनिक उद्योगों में प्रयोग किया जाता है, ये विशेषताएं हैं रासायनिक निष्क्रियता, इलैक्ट्रिकल और थर्मल इंसुलेशन, घर्षण का कम गुणांक, नॉन टॉक्सिक, अज्वलनशील, विकीरण के प्रतिरोध, स्थिर और गतिशील घर्षण का कम स्तर और व्यापक आवर्ती रेंज के दौरान उत्कृष्ट विद्युतीय विशेषताएं हैं।

ग. जांच के अधीन उत्पाद

8. जांच के अधीन उत्पाद और जो लागू पाटनरोधी शुल्क को कथित रूप से परिवर्तित कर रहा है (जिसे पी यू आई भी कहा गया है), कोरिया से निर्यातित पोलिटेट्राफ्लूरोएथीलीन (पी टी एफ ई) है। पोलिटेट्राफ्लूरोएथीलीन (पी टी एफ ई) को सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम के अंतर्गत उप शीर्ष सं. 390461 तथा उप शीर्ष सं. 39046100 के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और जांच के दायरे पर किसी भी प्रकार से बाध्यकारी नहीं है।

घ. घरेलू उद्योग

9. आवेदन मेसर्स गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है। आवेदक भारत में एक प्रमुख निर्माता है, जो भारत में विषय वस्तुओं के कुल उत्पादन का 99% से अधिक का लेखा-जोखा रखता है। आवेदक ने दावा किया है कि यह विषय के किसी भी निर्यातक या निर्माता से संबंधित देश में या भारत में पीयूसी या पीयूआई के किसी भी आयातक से संबंधित नहीं है। दूसरी कंपनी, जिसका नाम है, हिंदुस्तान फ्लूरोकार्बन लिमिटेड, जो विषय वस्तु का उत्पादन भी करती है, कुल उत्पादन का 1% से भी कम का उत्पादन करती है।

ड. मौजूदा उपाय

10. मौजूदा पाटनरोधी उपाय दिनांक 12 अप्रैल, 2016 की अधिसूचना सं. 15/2/2015 द्वारा लगाए गए थे, जिन्हें केन्द्र सरकार द्वारा दिनांक 6 जून, 2016 की अधिसूचना सं. 23/2016-सीमाशुल्क द्वारा लगाया गया था और दूसरी निर्णायक समीक्षा जांच के अनुपालन में कथित रूप से परिवर्तित किए जाने के कारण दिनांक 16 मई, 2017 की अधिसूचना सं. 22/2017 द्वारा आगे संशोधित किया गया था।

च. कथित परिवर्तन के आधार

11. परिवर्तनारोधी जांच के लिए आवेदन दिनांक 6 जून, 2016 की अधिसूचना सं. 23/2016-सीमाशुल्क द्वारा विचाराधीन उत्पाद पर लागू मौजूदा पाटनरोधी शुल्क तथा मौजूदा पाटनरोधी शुल्क की परिवर्तन के संबंध में विचाराधीन उत्पाद के लिए दिनांक 16 मई, 2017 की अधिसूचना सं. 22/017 द्वारा आगे संशोधित शुल्क की अवधि बढ़ाने के अनुरोध के साथ दायर किया गया है। आवेदक ने परिवर्तनारोधी जांच की मांग करते हुए निम्नलिखित कारण/साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं :-
 - क. व्यापार की प्रवृत्ति में भारी बदलाव हुआ है जिसके द्वारा कोरिया से आयातों में 2018 से भारी वृद्धि हुई है। यह दावा किया गया है कि ऐसे आयातों के लिए शुल्क लागू होने से इतर कोई आवश्यक कारण या औचित्य नहीं है।
 - ख. कोरिया में कोई भी ज्ञात उत्पादक पूर्णकालिक उत्पादक कार्यकलाप नहीं कर रहा है। यह भी दावा किया गया है कि कोरिया गणराज्य से प्रेषित पी टी एफ ई के निर्यात रूस में पर्याप्त रूप से उत्पादित किए गए हैं और तत्पश्चात् कोरिया में प्रसंस्कृत किए गए तथा उसके बाद कोरिया में उद्भूत वस्तु के रूप में भारत को निर्यातित हैं। आवेदक ने कोरिया में भांडागार की मौजूदगी का साक्ष्य उपलब्ध कराया है जो रूसी उत्पादक से संबंधित किसी कंपनी के स्पष्ट रूप से स्वामित्व में है।
 - ग. कोरिया से आयात पाटित कीमतों पर हुए हैं और घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती कर रहे हैं और परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहे हैं।
12. आवेदक ने जांच की शुरुआत की तारीख से शुल्क को पूर्वव्यापी रूप से लागू करने का अनुरोध भी किया है।
13. प्राधिकरण आवेदक द्वारा प्रदान की गई प्रथम दृष्टया सबूतों के आधार पर, नोट करता है कि व्यापार के पैटर्न में बदलाव हुआ है जिसमें कोरिया से आयात शुरू हुआ है और 2018 के बाद से किसी भी पर्याप्त कारण या आर्थिक औचित्य और ज्ञात के बिना एक महत्वपूर्ण स्तर तक बढ़ गया है। पूर्ण विकसित उत्पादन गतिविधि और मौजूदा एंटी-डंपिंग उपाय के उपचारात्मक प्रभाव को कम करना।

छ. जांच की शुरुआत

14. दक्षिण कोरिया से आयात के संबंध में आवेदक द्वारा विधिवत पुष्ट आवेदन के आधार पर और व्यापार के पैटर्न में परिवर्तन और मौजूदा एडी माप के उपचारात्मक प्रभाव को कम करने से संतुष्ट होने के आधार पर, प्राधिकरण ने दक्षिण कोरिया से आयातित विषय वस्तुओं पर रूस से आयात पर मौजूदा डंपिंग रोधी शुल्क के विस्तार पर विचार करने के लिए अधिनियम की धारा 9 ए (1 ए) और नियम 25 और 26 के अनुसार एक एंटी-सर्कुलेशन जांच शुरू की है।
15. प्राधिकरण नियमों के नियम 27 (3) के अनुसार इस जांच की शुरुआत की तारीख से दक्षिण कोरिया से आयात पर माप के विस्तार की सिफारिश करने पर भी विचार कर सकता है। प्राधिकरण इस समीक्षा के पूरा होने तक दक्षिण कोरिया से निर्यात किए गए विषय वस्तुओं के सभी निर्यातों पर अनंतिम मूल्यांकन की सिफारिश करता है।

झ. जांच की अवधि

16. वर्तमान जांच के लिए जांच की अवधि (पीओआई) अप्रैल 2019- दिसंबर 2019 (9 महीने) है और चोट की अवधि अप्रैल 2016 - मार्च 2017, अप्रैल 2017 - मार्च 2018, अप्रैल 2018 - मार्च 2019 की अवधि को कवर करेगी। POI। POI को 9 महीने मानते हुए माना गया है कि AD झूटी जून 2021 तक अस्तित्व में है।

ट. देश

17. वर्तमान जांच में शामिल देश कोरिया गणराज्य (कोरिया आर पी) है।

ठ. सूचना प्रस्तुत करना

18. संबद्ध देश में निर्यातकों, भारत में उनके दूतावास के जरिए संबद्ध देश की सरकार, भारत में उत्पाद से संबंधित समझे जाने वाले ज्ञात आयातकों और प्रयोक्ताओं को नीचे निर्धारित की गई समय सीमा के भीतर विहित प्रपत्र में एवं ढंग से संगत सूचना प्रस्तुत करने के लिए अलग से लिखा जा रहा है।
19. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी नीचे दी गई समय सीमा के भीतर विहित प्रपत्र और ढंग से इस जांच से संगत सूचना प्रस्तुत कर सकता है।

20. सूचना/अनुरोध निम्नलिखित को प्रस्तुत किए जा सकते हैं :

निर्दिष्ट प्राधिकारी
व्यापार उपचार महानिदेशालय
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
चौथा तल, जीवन तारा बिल्डिंग,
5, संसद मार्ग, नई दिल्ली- 110001

21. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी पक्षकार को अन्य पक्षकारों को उपलब्ध कराए जाने के लिए उसका एक अगोपनीय अंश प्रस्तुत करना भी अपेक्षित है।

ड. समय-सीमा

22. वर्तमान जांच से संबंधित कोई सूचना लिखित रूप में प्राधिकारी को भेजी जाए तथा वह नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 30 दिन के भीतर ऊपर उल्लिखित पते पर प्राधिकारी को पहुंच जानी चाहिए। तथापि, यह भी नोट किया जाए कि उक्त उप नियम के स्पष्टीकरण के अनुसार सूचना और अन्य दस्तावेज मंगाने वाले नोटिस को निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा उसे भेजे जाने वाली तारीख अथवा निर्यातक देश के उचित कूटनीतिक प्रतिनिधि को हस्तांतरित किए जाने की तारीख से एक सप्ताह के भीतर प्राप्त हुआ माना जाएगा। यदि विहित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है या प्राप्त सूचना अधूरी होती है तो प्राधिकारी नियमावली के अनुसार रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।
23. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्वारा वर्तमान मामले में अपने हित (हित के स्वरूप सहित) की सूचना देने और उपर्युक्त समय सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर देने की सलाह दी जाती है।

ढ. गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

24. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने या गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार को नियमावली के नियम 7(2) और इस संबंध में जारी की गई व्यापार सूचनाओं के अनुसार उसका अगोपनीय अंश भी साथ में प्रस्तुत करना अपेक्षित है। उपर्युक्त का पालन न करने पर उत्तर/सत्र को अस्वीकार किया जा सकता है।
25. प्रश्नावली के उत्तर सहित प्राधिकारी के समक्ष कोई अनुरोध (उससे संलग्न परिशिष्ट/अनुबंध सहित) प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों के लिए उसके किसी भाग के संबंध में "गोपनीयता" का दावा करने के मामले में निम्नानुसार दो अलग-अलग सैट प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा:-
- (क) गोपनीय रूप से अंकित एक सैट (शीर्षक, सूची, पृष्ठ संख्या आदि); और
- (ख) अगोपनीय रूप में अंकित दूसरा सैट (शीर्षक, सूची, पृष्ठ संख्या आदि)।
26. "गोपनीय" या "अगोपनीय" अनुरोधों पर स्पष्ट रूप से प्रत्येक पृष्ठ पर "गोपनीय" या "अगोपनीय" अंकित होना चाहिए। ऐसे अंकन के बिना प्रस्तुत सूचना को प्राधिकारी द्वारा अगोपनीय माना जाएगा और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसी अगोपनीय सूचना का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे। दोनों पाठों की हार्ड कॉपियों के साथ साफ्ट कॉपियां चार (4) सैट में प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित होगा।
27. गोपनीय पाठ में ऐसी समस्त सूचना होगी जो स्वाभाविक रूप से गोपनीय है और/अथवा ऐसी अन्य सूचना जिसका ऐसी सूचना के प्रदाता द्वारा गोपनीय होने का दावा किया गया है। स्वाभाविक रूप से गोपनीय होने का दावा की गई सूचना या अन्य कारणों से गोपनीयता का दावा की गई सूचना के संबंध में सूचना प्रदाता को प्रदत्त सूचना के साथ ऐसे कारणों का विवरण प्रस्तुत करना होगा कि उस सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता है।
28. अगोपनीय रूपांतरण को उस सूचना, जिसके बारे में गोपनीयता का दावा किया गया है, पर निर्भर रहते हुए अधिमानतः सूचीबद्ध या रिक्त छोड़ी गई (यदि सूचीबद्ध करना व्यवहार्य न हो) और सारांशीकृत गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय रूपांतरण की अनुकृति होना अपेक्षित है। अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना

चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना की गई विषय वस्तु को तर्कसंगत ढंग से समझा जा सके। तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रदाता पक्षकार यह इंगित कर सकते हैं कि ऐसी सूचना का सारांश संभव नहीं है और प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार इस आशय के कारणों का एक विवरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए कि सारांश क्यों संभव नहीं है।

29. प्रस्तुत सूचना के स्वरूप की जांच करने के बाद प्राधिकारी गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध अपेक्षित नहीं है अथवा सूचना प्रदाता उक्त सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्य रूप में अथवा सारांश रूप में उसके प्रकटन को प्राधिकृत करने का अनिच्छुक है तो वह ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।
30. सार्थक अगोपनीय रूपांतरण के बिना या गोपनीयता के दावे के बारे में यथोचित कारण के विवरण के बिना किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा।
31. प्रदत्त सूचना की गोपनीयता की जरूरत से संतुष्ट होने और उसे स्वीकार कर लेने के बाद प्राधिकारी ऐसी सूचना के प्रदाता पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना किसी पक्षकार को उसका प्रकटन नहीं करेंगे।

ण . सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

32. नियमावली के नियम 6 (7) के अनुसार कोई हितबद्ध पक्षकार उस सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकता है जिसमें अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय रूपांतरण रखे गए हैं।

ठ. असहयोग

33. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है अथवा उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी ऐसे हितबद्ध पक्षकार को असहयोगी घोषित कर सकते हैं और अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं तथा केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

भूपिन्दर एस. भल्ला, अपर सचिव एवं निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 16th April, 2020

Case No. AC-01/2020

Subject: Initiation of Anti-Circumvention investigation concerning alleged circumvention of anti-dumping duty imposed on the imports of “Polytetrafluoroethylene” (PTFE) originating in or exported from Russia by imports of “Polytetrafluoroethylene” (PTFE) exported from Korea RP.

F. No. 07/07/2020-DGTR.—

1. M/s Gujarat Fluorochemicals Limited (hereinafter referred to as the “Applicant”) has filed an application before the Designated Authority (hereinafter also referred to as the “Authority”), on behalf of the domestic industry, in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter also referred as the “Act”) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time (hereinafter also referred as the “Rules”), alleging that the anti-dumping duties imposed on imports of Polytetrafluoroethylene (PTFE) (hereinafter also referred to as “product under consideration” or “PUC” or “subject goods”), originating in or exported from Russia (hereinafter also referred to as the “subject country”) is being circumvented by way of imports of PTFE exported from Korea RP (hereinafter also referred to as Product Under Investigation or “PUI”).

A. Background

2. The Designated Authority notified final findings recommending definitive anti-dumping duty on import of Polytetrafluoroethylene (PTFE) vide Notification Number 21/1/1998 dated 13th October, 1999, originating in or exported from Russia and definitive Anti-dumping duty was imposed on the subject goods vide Customs Notification No. 141/99-Customs dated 30th December 1999.
3. The Authority recommended continued imposition of the anti-dumping duties vide Notification No. 15/6/2003-DGAD dated the 7th October, 2004 which was imposed by the central Government vide Notification No. 110/ 2004-Customs dated 18th Nov, 2004, pursuant to first sunset review investigation.
4. The Authority recommended continued imposition of the anti-dumping duties vide Notification No. 15/30/2008-DGAD dated the 26th February, 2010 which was imposed by the Central Government vide Notification No. 57 /2010-Customs dated 3rd May, 2010, pursuant to second sunset review investigation.
5. The Authority recommended continued imposition of the anti-dumping duties vide Notification No. 15/2/2015-dated 12th April, 2016 which was imposed by the Central Government vide Notification No. 23/2016-Customs dated 6th June, 2016 and further amended by Notification No. 22/2017 dated 16th May 2017, pursuant to second sunset review investigation. The duties are in force till 5th June 2021.

B. Product under consideration

6. The product under consideration in the present investigation, as defined in the last conducted sunset review investigation is "Polytetrafluoroethylene (also referred to as 'PTFE' or 'product under consideration') originating in or exported from Russia. The duties are in force till 5th June, 2021.
7. PTFE is produced in various grades, such as moulding grade, fine powder, aqueous dispersion and compound grades of filled grades. PTFE is primarily used in electrical, electronic, mechanical and chemical industries for their unique characteristics which are chemical inertness, electrical and thermal insulation, low coefficient of friction, nontoxic, non-flammable, resistance to radiation, low level of static and dynamic friction and outstanding electrical properties over a wide frequency range.

C. Product under Investigation

8. The Product under Investigation and which allegedly circumventing the anti-dumping duties in force (also referred to as 'PUI') is Polytetrafluoroethylene exported from South Korea. Polytetrafluoroethylene (PTFE) is classified under subheading no 390461 under Customs Tariff Act and at subheading no. 39046100. Customs classifications are indicative only and, in no way, binding on the scope of the investigations.

D. Domestic Industry

9. The application has been filed by M/s Gujarat Fluorochemicals Ltd. The Applicant is a major producer in India accounting for more than 99% of the total production of the subject goods in India. The Applicant has claimed that it is not related to any exporter or producer of the subject goods in the subject country or any importer of the PUC or PUI in India. The other company, namely, Hindustan Fluorocarbons Ltd., which also produces the subject goods has production less than 1% of the total production. On the basis of the information available, the Authority is satisfied that the application has been made 'by or on behalf of the domestic industry' in terms of Rule 2 (b) and Rule 5(3) of the Rules.

E. Existing Measures

10. The existing anti-dumping measures imposed *vide* Notification No.15/2/2015-dated 12th April, 2016 which was imposed by the Central Government vide Notification No.23/2016-Customs dated 6th June, 2016 and further amended by Notification No. 22/2017 dated 16th May 2017, pursuant to second sunset review investigation, are allegedly being circumvented.

F. Grounds for Alleged Circumvention:

11. The application for anti-circumvention investigation has been filed seeking extension of existing anti-dumping duty levied on product under consideration vide Notification No.23/2016-Customs dated 6th June, 2016 and further amended by Notification No. 22/2017 dated 16th May 2017 on Product under Investigation circumventing the existing anti-dumping duty. The applicant has furnished following reasons/ evidence seeking anti-circumvention investigation:
 - a) There is significant change in the pattern of trade whereby imports from Korea have increased significantly since 2018. It has been claimed that there is no due cause or justification for these imports other than the duty in force.
 - b) There is no known producer in Korea undertaking full-fledged production activities. It has been claimed that exports of PTFE consigned from Korea RP are substantially produced in Russia and thereafter processed in Korea and then exported to India as goods originating in Korea. Applicant has provided evidence of existence of a warehouse in Korea, which is apparently owned by an entity related to the Russian producer.
 - c) The imports from Korea are at dumped prices and are undercutting the prices of the domestic industry and consequently adversely impacting the domestic industry by undermining the remedial effects of the existing anti-dumping measure.
12. The Applicant has also requested retrospective imposition of duty from the date of initiation of investigation.
13. The Authority on the basis on the prima facie evidences provided by the Applicant, notes that there is change in the pattern of trade wherein imports have commenced from Korea and increased to a significant level since 2018 without any sufficient cause or economic justification and known full-fledged production activity and undermining of the remedial effects of the existing anti-dumping measure.

G. Initiation

14. On the basis of the duly substantiated application by the Applicant regarding imports from South Korea and having satisfied itself on the change in pattern of trade and undermining of the remedial effect of the existing AD measure, the Authority hereby initiates an Anti-Circumvention investigation in accordance with Section 9A (1A) of the Act and Rule 25 & 26 of the Rules to consider extension of existing anti-dumping duty on imports from Russia to the subject goods imported from South Korea.
15. The Authority may also consider recommending extension of the measure on imports from South Korea from the date of initiation of this investigation in accordance with the Rule 27 (3) of the Rules. The Authority recommends provisional assessment on all exports of the subject goods exported from South Korea till the completion of this review.

H. Period of Investigation:

16. The period of investigation (POI) for the present investigation is April 2019- December 2019 (9 Months) and the injury period will cover the periods April 2016 - March 2017, April 2017 - March 2018, April 2018 - March 2019 and the POI. The POI has been considered as 9 months keeping in view that the AD duty is in existence only till June 2021.

I. Country

17. The country involved in the present investigation is Republic of Korea (Korea RP).

J. Submission of Information

18. The exporters in the subject country, the Government of the subject country through its embassy in India, the importers and users in India known to be concerned with the product are being addressed separately to submit relevant information in the form and manner prescribed within the time limit set out below.
19. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the prescribed form and manner within the time limit set out below.

20. The information/submission may be submitted to:

The Designated Authority
Directorate General of Trade Remedies
Ministry of Commerce & Industry
Department of Commerce
4th Floor, Jeevan Tara Building,
5, Parliament Street New Delhi – 110001

21. Any party making any confidential submission before the Authority is required to submit a non-confidential version of the same to be made available to the other parties.

K. Time Limit

22. Any information relating to the present investigation should be sent in writing so as to reach the Authority at the address mentioned above within thirty days from the date of receipt of the notice as per Rule 6(4) of the Rules. It may, however, be noted that in terms of explanation of the said sub rule, the notice calling for information and other documents shall be deemed to have been received one week from the date on which it was sent by the Designated Authority or transmitted to the appropriate diplomatic representative of the exporting country. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the Rules.
23. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses within the above time limit.

L. Submission of information on confidential basis

24. Any party making any confidential submission or providing information on confidential basis before the Authority, is required to simultaneously submit a non-confidential version of the same in terms of Rule 7(2) of the Rules and the Trade Notices issued in this regard. Failure to adhere to the above may lead to rejection of the response/sessions.
25. The parties making any submission (including Appendices/Annexures attached thereto), before the Authority including questionnaire response, are required to file the same in two separate sets, in case "confidentiality" is claimed on any part thereof:
- a. one set marked as Confidential (with title, number of pages, index, etc.), and
 - b. the other set marked as Non-Confidential (with title, number of pages, index, etc.).
26. The "confidential" or "non-confidential" submissions must be clearly marked as "confidential" or "non-confidential" at the top of each page. Any submission made without such marking shall be treated as non-confidential by the Authority, and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect such submissions. Soft copies of both the versions will also be required to be submitted, along with the hard copies in four (4) sets of each.
27. The confidential version shall contain all information which is by nature confidential and/or other information which the supplier of such information claims as confidential. For information which are claimed to be confidential by nature or the information on which confidentiality is claimed because of other reasons, the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed.
28. The non-confidential version is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out (in case indexation is not feasible) and summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on confidential basis. However, in exceptional circumstances, the party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summary, and a statement of reasons why summarization is not possible must be provided to the satisfaction of the Authority.

29. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied the request for confidentiality is not warranted or if the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.
30. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without good cause statement on the confidentiality claim shall not be taken on record by the Authority.
31. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided, shall not disclose it to any party without specific authorization of the party providing such information.

M. Inspection of Public File

32. In terms of Rule 6(7) of the Rules, any interested party may inspect the public file containing non-confidential version of the evidence submitted by other interested parties.

N. Non-cooperation

33. In case any interested party refuses access to and otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may declare such interested party as non-cooperative and record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

BHUPINDER S. BHALLA, Addl. Secy. & Designated Authority